

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

₹№ 64]

नई दिल्ली, सोमबार, फरवरी 3, 1997/मार्घ 14, 1918

No. 64]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 1997/MAGHA 14, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1997

(आयकर)

का.आ. 74( अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकधाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और तूर्की गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार, उक्त करार के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 1-के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् माह फरवरी, 1997 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हो गया है:

इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

#### अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्य अपवंचन को रोकने के लए

भारत गणराज्य की सरकार

और

तुर्की गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्मन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

274 GV97

### अनुच्छेष - 1

### वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अधवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

# बनुच्छेद - 2

### श्रामिल कर

- यह करार उन सभी करों पर लागू होगा जो कि प्रत्येक सीवदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाए जाते हैं, इस बात को ध्यान में न रसते हुए कि वे किस प्रकार लगाए जाते हैं।
- 2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर लगने वाले कर उद्यमों द्वारा अदा की गई पगार अथवा वेतनों की सकल राश्चियों पर लगने वाले करों के साथ-साथ ही पूँजी वृद्धि पर लगने वाले कर भी शामिल हैं।
- जिन मौजूदा करों पर विशेष रूप से यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :-
  - **१क** श्रमारत के मामले में :
    - हैं। हैं आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी श्रामिल है ;
    - §जिसे **इ**सके बाद 'भारतीय कर" कहा जाएगा§
  - - ∦ां श्राय कर श्रोलिर वर्गिसी है;
    - हों। हिनगम कर हकुरूपलर वर्गिसीह ;
    - § iii § आयकर और निगम कर पर लगने वाली कोई लेवी
      - **∮जिसे इसके बाव "तुर्किश कर" कहा जाएगा ∮** [
- 4- यह करार किसी भी समस्य अधवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो किसी भी संविदाकारी राज्य के बारा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अधवा उनके स्थान पर लगाए जाएं । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए जाते हैं ।

# अनुच्छेद - 3

### सामान्य ठिप्पनियाँ

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
- १ कि १ भारत पर से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल राज्य-क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके उत्पर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भारत के प्रमुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हों ।
- हस है "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पर्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार तुर्की अधवा भारत अभिग्रेत है;
- १ग है "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अधवा तुर्किश कर अभिप्रेत है;
- हिंघ हैं "व्यक्ति" पर में कोई व्यप्तिट, कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे सम्बद्ध संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य पक इकाई माना जाता है;
- §ड · § "कम्पनी" पद से कोई भी पेसा निगमित निकाय अथवा कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जिसे सम्बद संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता हो ;
- हच हैं "पंजीकृत कार्यालय" पद से वही अर्थ होगा जो प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत होगा;
- १छ । "राष्ट्रिक" पद से अमिप्रेत है किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत उस सीवदाकारी राज्य में प्रकृत कानूनों से उस रूप में प्रकृत होती हो ;
- हुज हैं " प्रक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पर्दों से कृमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी बरा संचलित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी बरा संचालित कोई उद्यम अभिग्रेत हैं ;

- १झ१ "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत हैं :
  - § i § भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय § राजस्व विभाग § अधवा उनका प्रधिकृत प्रतिनिधि ;
  - § i i i है तुर्की के मामले में वित्त मंत्री अथवा उसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- श्रा "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिग्रेत है, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी वायुयान अथवा जलयान द्वारा किया गया कोई भी परिवहन, उस स्थिति को छोड्कर जब ऐसे जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।
- 2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमें परिमाधित नहीं है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तब तक वही अर्थ होगा, जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिनपर यह करार लागू होता है।

# अनुच्छेव - 4

#### निवासी

- इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा क्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, कानूनी मुख्य कार्यालय हंपंतीकृत कार्यालय है, प्रबंध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौदी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है।
  उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:

  - शस्त यदि उस राज्य को, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं निश्चित नहीं किया जा
    सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास−
    गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें
    वह आदतन रहता है;

- ∛घ । यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अधवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।
- 3. जहां व्यष्टि से झिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार के अनुच्छेद 25 के अनुसार पारस्परिक सहमित से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

# अनुच्छेव - 5

### स्थायी संस्थापन

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद से अभिप्रेत है कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके क्वरा किसी उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंश्वतः चलाया जाता है ।
- 2 ,"स्थायी संस्थापन" पद में विश्वेषतया निम्नलिसित शामिल होंगे :
  - §क ह प्रबंध का कोई स्थान ;
  - **∛ख** । कोई शाखा ;
  - १ग को ई कार्यालय ;
  - ४घ ४ कोई कारलाना ;
  - ≬ड•≬ कोई कार्यशाला ;
    - §च इ कोई सान, तेल अथवा गैस कोई कुआं, कोई सदान अथवा प्रकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
  - §छ§ कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की सोज अथवा विदोहन करने के लिए किया जाता हो ;
  - §ज किसी व्यक्ति से संबंधित कोई माण्डागार जिसमें अन्यों के लिए भाण्डागारण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों :
  - ईझ कोई परिसर जिसका प्रयोग विकय स्थल अधवा सरीव आदेशों को प्राप्त करने अधवा मंगवाने के लिए किया जाता है :

- हिंचे हैं । हैं कोई मवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबोधत पर्यवेक्षी कार्यकलाप आते हैं, जहां ऐसा भवन-स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप हैं अन्य ऐसे भवन-स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों, यदि कोई हों के साथ है छः महीने से अधिक अवधि के लिए बलता रहता है; अथवा
  - हां। इं जहां ऐसे परियोजनों अधवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप जो मशीनरी अधवा उपकरण की बिकी के लिए प्रासींगक हैं, कम से कम छः माह से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं, परन्तु परियोजना अधवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए अदा करने योग्य प्रमार मशीनरी और उपकरण के बिकी मृत्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

ब अर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए एक संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यवसाय का चलाया जाना भी समझा जाएगा यदि वह उस राज्य में सिनज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा निष्कर्षण अथवा उत्पादन के संबंध में छः मास या अधिक के लिए सेवाएं प्रदान करता हो अथवा इस्तेमाल की गई अथवा इस्तेमाल करने के लिए संयंत्र और मशीनें उपलब्ध कराता हो ।

- 3. इस अनुस्केद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिसित को शामिल नहीं माना जाएगा :
  - किसी उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा
    कभी-कभार उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;

  - शग
    शामित किए जाने के प्रयोजनार्ध उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं का स्टॉक रखना ;

  - §ड ∙ § उद्यम के लिए केवल विद्वापन देने, सूचना प्रदान करने, वैद्वानिक अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के कियाबलायों के लिए जो कि प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, के लिए निश्चित स्थान रखना ;

- १७१ उप-पैराग्राफ १क१ से १च१ में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार
   के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाब करना ।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के प्लेन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उस उद्यम का प्रथमोहिलांबित राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि
  - हैक है वह उस राज्य में उस उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्रधिकार रखता हो और आभ्यासिक रूप से उस प्रधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अध्यक्ष पण्य-वस्तुओं के क्रय तक ही सीमित न हो:
  - §स 

    § उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो परन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अधवा

    पण्य-वस्तुओं का आध्यासिक रूप से ऐसा स्टॉक रखता हो जिसमें से वह व्यक्ति उस

    उद्यम की ओर से नियमित माल अधवा पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो; अधवा
  - वह प्रथमोल्लिसित राज्य में पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम के लिए अथवा
     उस उद्यम तथा अन्य उद्यमों के लिए अभ्यासिक रूप से आदेश प्राप्त करता हो जो
     उस उद्यम को नियंत्रित करते हों अथवा उससे नियंत्रित होते हों अथवा उसी प्रकार के
     सामान्य नियंत्रण में आते हों जिसमें कि वह उद्यम आता है ।
- 5. पक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अधवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।
- 6. यि कोई कम्पनी जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अधका किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अधवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में श्वाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अधवा अन्यधा कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

## अनुच्छेष - 6

### अचल सम्प्रित से आय

- 2. "अचल सम्पित्त" पद का अर्थ वही होगा जो उस सीवदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है, जिसमें संबंधित सम्पित्त रियत है । इस पद में, किसी भी हालत में ये शामिल होंगे-अचल सम्पित्त के अवसाधन के रूप में सम्पित्त, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर मछली फकड़ने के सभी प्रकार के स्थल, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पित्त संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पित्त को भोगने के अधिकार और सिनज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अध्या कार्य करने के अधिकार के प्रतिपत्त के रूप में परिकर्तनीय अध्या नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं और विमान अचल सम्पित्त नहीं माने जाएंगे ।
- प्रिताग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पित्त के प्रत्येक उपयोग जो किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

# अनुच्छेद-7

### कारोबार से लाम

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लामों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लामों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लामों के केवल उतने अंग पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुआ माना जाएगा ।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वहां एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिनन उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन

- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लागों का निर्धारण करने में उन सर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ सर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार सर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासिनक ब्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस सज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों।
- 4- कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं सरीदी हैं।
- 5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्ध स्थाया संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लामों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पदाति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।
- 6. जहां ताभों में आय की ऐसी मर्वे भी शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य अनुक्छेवों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुक्छेदों के उपबंध इस अनुक्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

## अनुच्छेद - 8

## जडाजरानी तया वायु परिवडन

- 1. किसी सीवदांकारी राज्य के किसी उद्यम बरा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से प्राप्त लामों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्य, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का अर्थ है पैराग्राफ 1 में निहित किसी उद्यम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों या पट्टेदारों अथवा चार्टररों द्वारा कमश्रः जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुचन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ. जिनमें निम्नलिशित शामिल हैं :-

  - १ सं १ पेरे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्यकलापः और
  - ग्रेग जलयानों अथवा वायुयानों को किराये पर देना जो ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित
     किसी कार्यकलाप के लिए आनुषंगिक है ।
- 3. पैराग्राफ 1 में निहित किसी सीववाकारी राज्य के किसी उद्यम व्रारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित उसके उपयोग, रख-रसाथ अथवा किराये के आधानों हैंट्रैलर्स, बर्गेज तथा आधानों के परिवहन से सम्बद्ध उपस्कर सहित है से प्राप्त लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

- 4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन फर्नेसी में भाग लेने से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।
- इस अनुद्धेद के प्रयोजनार्ध, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लामों के रूप में माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुद्धेद 11 हब्याजह के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

# अनुच्छेद - ९ सहयोगी उद्यम

- 1 जहां
  - इंक
     इंक

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणि ज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थित में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेंगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्ते इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गयी होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों में वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

## अनुच्छेद - 10

### तमांश

- एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए तक्ष्मांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
- 2. तथापि, ऐसे लामांशों पर उस सीववाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लामांश अवा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लामांश का हिताधिकारी-स्वामी है, तो इस प्रकार प्रमारित कर लामांशों की सकल ग्रीश का 15 प्रतिश्वत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लागों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पद्देगा जिनमें से लाभों का भुगतान किया जाता है ।

- 3. इस अनुच्छेव में यथाप्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों, "जेयोसेन्स" श्रेयरों अथवा "जेयोसेन्स" राष्ट्स, प्रवर्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में तथा निवेश-निधि और निवेश-न्यास से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।
- 4. फ संविदाकारी राज्य की कोई कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य में वहां स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाती हो, उसके लामों पर अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कर लगाने के बाद, उसकी बकाया राशि पर, उस संविदाकारी राज्य में जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार कर लगाया जाएगा।
- \$ . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि लामांश का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लामांश अदा करने वाली कम्पनी वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से निवासी है और जिस धारणधिकार के बारे में लामांशों की अवायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुस्केष 7 के उपबंध लागू होंगे।

# अनुच्छेब - 11

#### स्याज

- 1. फ संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविद्याकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है तथा यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हित्रमागी-स्वामी हो, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नितिष्ठित से अधिक नहीं होगा :
  - हैक है व्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐसा व्याज किसी बैंक अधवा किसी वित्तीय संस्थान बारा मंजूर किए गए किसी भी प्रकार के ऋण पर अदा किया जाता है ; और
  - **१स** } अन्य सभी मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत ।
- उ. पैराग्राफ 2 के होते हुए भी, एक संधिवाकारी राज्य में उव्भूत होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिसित वारा प्राप्त किया गया हो और उनके हितभागी स्वामित्व में हो कि वृसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अधवा कोई स्थानीय
  - प्राधिकरण ; अथवा
  - १ स १ दूसरे सीवदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक ; अधवा
  - १ग१ तुर्की का निर्यात –आयात बैंक १ पिजम बैंक १ तथा भारत का निर्यात आयात बैंक ।
- 4. इस अनुद्धेव में यथा-प्रयुक्त "ज्याज" शब्द से अभिप्रेत है- प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्रप्त आय, चाहे वे बंधक द्वरा प्रतिमृत हों अध्या नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लक्ष्मों में भागीदारी का कोई अधिकार प्रप्त हो अध्या नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभृतियों से प्रप्त आय और बंध-पत्रों अध्या ऋण-पत्रों से प्रप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंध-पत्रों से संबंधित प्रिमियम शामिल हों तथा उधार दी गयी मुद्रा से प्रप्त अन्य आय को ब्याज के रूप में माना जाएगा।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपकंप उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि क्याज का हितमागी स्थामी, सीववाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे सीववाकारी राज्य में जिसमें क्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अधवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयिक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण-वावे के बारे में क्याज अदा किया गया हो वह इस फ्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रमावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपवंध लागू होंगे।

- 6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रमाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है और ऐसा व्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान वहन किया जाता है, तब ऐसा व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा निसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हो ।
- 7. जहां, स्याज अवाकर्ता तथा हितभागी स्थामी के बीच अथथा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विश्वेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी ब्याज की एकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की एकम अदा की गयी है, उस एकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध महीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्थामी के बीच सहमित हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित एकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायिगयों के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सीवदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

### जन्छेद −12

### त्रयह्न्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

- 1. पक सींविवाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे सींववाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायिहटयों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार की रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सीववाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा परन्तु यदि रायहिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का प्राप्तकर्ता हितभागी-स्वामी हो, तो इस प्रकार प्रमारित कर रायहिट्यों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3. इस अनुद्धेव में यथा-प्रयुक्त "रायल्ये" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी काषीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगिधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्में, टेलीकिजन के संबंध में उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा वीडियो टेपें अथवा रेडियो प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए टेपें भी शामिल हैं, कोई पेंटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिन्यिक अथवा वैज्ञानिक उफ्करणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगिधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिन्यिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिग्रेत हैं।

- 4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अधवा परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं के लिए जिसमें तकनीकी सेवाओं अधवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में अदायिगयां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायिगयों से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी किसम की अदायिगयों से अभिप्रेत है।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे यदि रायल्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविद्याकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविद्याकारी राज्य में, जिसमें रायल्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति अथवा संविद्या के संबंध में रायल्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुक्छेद 7ं के उपबंध लागू होंगे।
- 6. एक संविद्याकारी राज्य में रायित्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायत्य और फीस अवा करने वाला स्वयं वह राज्य उसका कोई राजनैतिक उप-प्रमाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायत्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला व्यक्ति का चाहे वह किसी संविद्याकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविद्याकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायत्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित अधिकार, सम्पत्ति अथवा करार प्रभावी रूप से संबंधित है और ऐसी रायत्य तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायत्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायत्य अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविद्याकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थान स्थित हो ।
- 7. जहां अदाकर्ता और हितमागी स्वामी के बीच अधवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्य अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, इसके उपयोग, अधिकार तथा सूचना अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जिसके लिए इसकी अदायगी की जाती है, उस रकम से बद जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध न होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितमागी स्वामी के बीच सहमित हुई होती, वहां इस अनुद्धेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में रायिष्टियों अधवा तकनीकी सेवाओं के फीस के संबंध में अदा की गयी रकम का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों की ध्यान में ररखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

## अनुच्छेद -13

# पुँजीगत अमिलाम

- 1. अनुरुषेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलामों पर, जो एक संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलामों पर, जो सम्पत्ति एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्वतंत्र वैद्यवितक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन ∮अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाम भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।
- अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो ।
- 4. किसी ऐसी कंपनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अधिलामों पर, जिस की सम्पित प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- किसी पेसी कंपनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो एक सीवदाकारी राज्य की निवासी कंपनी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 6. पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 5 में उल्लिबित सम्पत्ति से भिन्न, किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है। तथापि, पूर्ववर्ती वाक्य में उल्लिबित तथा दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त पूँजीगत अभिलामों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि प्राप्त करने और अन्तरण करने के बीच की अवधि पक वर्ष से अधिक न हो।

# अनुच्छेव -14,

### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय निम्निलिखत पीरीस्थितियों को छोड्कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे सीयदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :
  - §क 

    यि उसे अपने कार्यकलार्षे के निम्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में पक

    निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में

    केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत

    हुई मानी जा सकती है; अथवा
  - ३स ३ यि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत "पिछले वर्ष" अथवा "आय के वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो यथास्थित के अनुसार उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में उसके बारा निष्पादित कार्यकलार्पों से प्राप्त होती हो ।
- 2. ''व्यावसायिक सेवापं'' पद में विशेषतः स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

# अनुच्छेव -15

### परावलम्बत वैद्यवितक सेवाएं

1. अनुद्धेद 16, 18, 19 तथा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बश्रर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

- 2. पैराग्राफ 1 के उपकंधों के होते हुए भी, एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सीवदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोहिलसित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा : यदि :
  - १क १ "प्राप्तकर्ता" तुर्की के मामले में संबंधित कैलेण्डर वर्ष के दौरान ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा हो, जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक न हो तथा जो भारत के मामले में संबंधित वित्त वर्ष में 183 दिनों तक मौजूद रहा हो ; और
  - । परिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अधवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का
    निवासी नहीं है ; और
  - ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के संबंध में नियोजक वारा कोई
     परिश्रमिक वहन नहीं किया जायेगा जो उसका दूसरे राज्य में स्थित है ।
- 3. इस अनुस्केद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पेत अधवा विमान पर विये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस सीववाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का पंनीकृत कार्यांलय हो ।

# अनुब्छेव -16

### निवेशकों की फीस

निवेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियाँ, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी क्रेस किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निवेशक-मंडल के सवस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो , उन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

# बनुव्छेव -17

## क्लाकार और बिलाड़ी

1. अनुच्छेय 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सीववाकारी राज्य के किसी निवासी वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई धियेटर, बलचित्र, रेडियो अधवा दूरदर्शन कलाकार अधवा किसी संगीतकार अधवा किसी बिलाई। के रूप में दूसरे सीववाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलाणें से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी बिलाड़ी बरा अपनी इस फ्रकार की हैसियत से किए गये वैयिक्तक कार्यकलाणों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा बिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अधितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुस्टेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा बिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं।

3. पक संविदाकारी राज्य में कलाकारों अथवा बिलाड़ियों बारा किए गए कार्यकलाणों से प्राप्त आय पर पराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में दौरा करने के बाद दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों अथवा राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण बारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पर्याप्त रूप से समर्पित हो। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आय केवल अन्य राज्य में ही कराधेय होगी।

# बनुष्टेव -18 गैर-सरकारी पैन्नन

- 1. पक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा उसके पिछले नियोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य के स्नोतों से प्राप्त अनुस्केद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से झिन्न किसी पेंशन अधवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लग सकेगा । यह उपबंध संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त जीवन वार्षिकियों पर भी लागू होगा ।
- 2. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटनाओं का बीमा करने के संबंध में अदा की गई पेंशनों और जीवन वाधिकियों और अन्य आवधिक अथवा प्रासीगक अवायिगयों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
- उ॰ "पॅश्वन" पद से पिछले नियोजन के लिए प्रतिफल के रूप में अधवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपृत्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है ।
- 4. "वार्षिकी" पद से जीवन-काल में अथवा किसी विनिर्विष्ट अथवा अभिनिश्चित समयाविध के दौरान धनराशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के दायित्व के अंतर्गत आविधक रूप में निश्चित समय पर अदायगी योग्य पक निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

## अनुच्छेद −19

### सरकारी सेवा के संबंध में परिश्रमिक तथा पेंजन

- कि किसी संविद्याकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यप्टि को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रमाग अथवा प्रधिकरण के तिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से मिन्न, पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।
  - इस के तथापि, ऐसे परिश्रमिक पर केवल दूसरे सीववाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा,
    यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यिष्ट उस राज्य का निवासी है, जो
    - 🖇 i 🖟 उस राज्य का एक राष्ट्रिक **है**; अधवा
    - § i i । प्रथमोिल्लिसत राज्य का राष्ट्रिक न होने के नाते, मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
- १०० १००१ किसी संविद्याकारी राज्य द्वारा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोच द्वारा उसमें से किसी व्यपिट को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रमाग अथवा प्राधिकरण के तिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।
  - १सं १ तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यवि
    व्यिष्ट उस अन्य राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।
- 3. अनुस्केव 15,16 और 18 के उपबंध किसी सींववकारी राज्य अधवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अधवा किसी स्थानीय प्राधिकरण वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

## जनुष्ठेव - 20

### जध्यापक और विद्यार्थी

- 1- ऐसे किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसिध्यक प्रशिक्ष को, जो किसी संविद्याकारी राज्य का एक राष्ट्रिक है और जो मात्र अपनी विक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए दूसरे संविद्याकारी राज्य में उपस्थित रहता है, अपने भरण-पोषण, विक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन से आय प्राप्त करता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बक्षर्ते कि ऐसी प्राप्तियां उस दूसरे राज्य के बाहर के खोतों से उद्भूत होती हैं।
- 2. इसी प्रकार, किसी अध्यापक अथवा किसी प्रशिक्षक द्वरा जो किसी संविदाकारी राज्य का पक राष्ट्रिक है और जो अध्यापन करने अथवा वैक्कानिक अनुसंधान करने के प्रमुख प्रयोजन के लिए किसी अवधि अथवा अवधियों के लिए जो दो वर्षों से अधिक न हो, अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए वैयक्तिक सेवाओं से होने वाले परिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बचर्ने कि ऐसी प्राप्तियां उस दूसरे राज्य के बाहर ब्रोतों से उद्भूत होती हैं।
- 3. ऐसे परिश्रमिक पर, जिसे कोई विद्यार्थी अधवा कोई प्रशिक्षार्थी जो किसी संविदाकारी राज्य में एक राष्ट्रिक है, अपनी शिक्षा अधवा प्रशिक्षण के संबंध में व्यवहार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए, तुर्की के मामले में, किसी कैलेण्डर वर्ष में 183 दिनों से अधिक की अवधि अधवा अवधियों के लिए और भारत के मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में 183 दिनों की अवधि के लिए दूसरे संविद्याकारी राज्य में किसी नियोजन से प्राप्त करता है, उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

### अनुच्छेष - 21

#### अन्य आवय

- 1. पैराग्राफ 2 के उपवंधों के अध्यथीन, एक सीववाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मर्वे, जहां-कहीं वे उव्भूत हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुक्तियों में स्फट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस सीववाकारी राज्य में कराधेय होंगी ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुस्त्रेव 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अञ्चल सम्पत्ति से प्राप्त आय से मिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि पेसी आय का प्राप्तकर्ता पक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सीवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से करोबार करता है और ऐसा अधिकार अधवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में पेसी आय अदा की जाती है, पेसे स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुस्त्रेव 7 के उपबंध लागू होंगे।

उ. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सीववाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदौं पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे सीववाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा ।

## अनुच्छेष - 22

### वोडरे कराधान का अपकरन

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रश्रुत्त कानून, संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे, सिवाय ऐसे मामलों को छोड्कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है ।
- शुक हैं जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनसार तुर्की में कर लगेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के वाच उस निवासी की आय पर तुर्की में अवा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर, कर से कटौती की अनुमति देगा । दोनों मामलों में, ऐसी कटौती की रकम, आयकर हकटौती दिए जाने से पूर्व यथासंगणित के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो कि ऐसी आय के कारण हो गिस पर तुर्की में कर लगाया जा सकता है ।
  - §स 

    श्रें जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार केवल तुर्की में कर लगेगा, वहां भारत उस आय को कर-आधार में शामिल कर सकता है, परन्तु आयकर के उस भाग को, जो तुर्की से प्राप्त की गई आय के कारण बनता है, आयकर से कटौती के रूप में अनुमति देगा ।
- उ॰ तुर्की के निवासियों के लिए बोहरे कराधान का अपकरण निम्न प्रकार से होगा :-
  - हिक है जहां तुर्की का कोई निवासी, उप-पैरा हिल है में आने वाली आय को छोड़कर, ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहां तुर्की, ऐसी आय को कर से छूट देगा, लेकिन उस व्यक्ति की क्षेम आय पर कर की रकम की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकेगा जो यदि ऐसी छूट प्राप्त आय को छूट प्रदान नहीं की गई है, लागू होती ;

§स ्र्रं जहां तुर्की का कोई निवासी पेसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के अनुच्छेव 10, 11, 12 और अनुच्छेव 13 के पैराग्राफ 6 के उपक्यों के अनुसार भारत में कर संगेगा, वहां तुर्की, उस व्यक्ति की आय पर भारत में प्रवत्त कर की रकम के बराबर रकम पर कर से कटौती के रूप में अनुमित वेगा ।

तथापि, ऐसी कटोतियाँ, कटोतियाँ विष जाने से पूर्व संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय के लिए उपयुक्त है, मिस पर भारत में कर लग सकेगा ।

### अनुस्केव - 23

#### सम-व्यवहार

पक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अधवा 1 -तत्संबंधी अफेदाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसी ही परिस्थितियों में, वैसे ही उपनंघों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। अनुस्छेद 10 के पैराग्राफ 4 के उपनंधों के अध्यधीन, एक सीववाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिश्यितियों में और उपकंधों के अधीन वैसे ही कार्य में संलग्न उद्यम को लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकृत हो । इस उपक्षंघ का यह अर्घ नहीं लगाया जाएगा कि इस करार के अनुस्केद 7 के पैराग्राफ 3 के उपनेधों के विरोध में नहीं होने के नाते, इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उपम के प्रथमोदिलाक्षित राज्य में स्थित किसी स्थायी-संस्थापन के लागों पर, कर की पेसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस वर से अधिक है जो प्रधमोत्सिबित सीववाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाओं पर लगाई जाती है । पक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पुनी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के पक अधवा पक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अधवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त सींवदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अधया अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्व है, जो प्रथमोहिलासत राज्य के अन्य समरूप उद्यमीं पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है इन उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि फ सीवदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि अन्य सीववाकारी राज्य के निवासियों को कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा परिवारिक जिम्मेदारियों के कारण किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छुटें, राहतें और कटौतियां मंजूर करे जो वह अपने निवासियों को मंजूर करता है।

## अनुच्छेव - 24

### सूचना का आवान-प्रवान

- 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रियकारी ऐसी सूचना का ह दस्तावेजों सोहत है आवान-प्रवान करेंगे, जो इस करार के उपवंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपवंधों को कायिन्यित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकृत नहीं हो ताकि विशेष स्प से ऐसे करों की धोसाधड़ी अथवा अपवंचन को रोका जा सके । किसी भी संविदाकारी राज्य करा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । तथािष, यिव सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलत: गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को हिननमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं है प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वस्ती करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद हों, जिन पर यह करार लागू होता है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों और तकनीकों को विकासित करेंगे पिनके बारे में सूचना का आदान-प्रवान किया जाएगा, जिनमें जहां-कर्षी उपयुक्त हो, कर-अपवंचन के संबंध में सूचना का अवान-प्रवान भी शामिल है।
- 2 · किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी सीवदाकारी राज्य पर निम्निलिखत वायित्व डालना नहीं होगा :-

  - ऐसी सूचना अथवा वस्ताकेंगों की सप्लाई करना जो उस अथवा वूसरे सीववाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
  - १ग१ ऐसी सूचना अथवा वस्तावेजों की सप्लाई करना जिसमें कोई व्यापारिक, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृत है।

# अनुच्छेव - 25

### परस्परिक करार कार्यविधि

- 1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है जो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में उपवारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है।
- 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपित उचित लगे और यदि वह स्वयं समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे करायान के निर्धारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुस्प नहीं है, दूसरे सीवक्कारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमित द्वारा इस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे सीवदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई समय-सीमा अथवा कियाविध संबंधी सीमा निर्धारण क्यों न हो बश्रतें कि दूसरे सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को यह अधिसूचना प्राप्त हो गई हो कि ऐसा कोई मामला इस कराधेय वर्ष के अंत से पांच वर्षों के भीतर उपस्थित हो जिससे यह मामला संबंधित है।
- उत्पन्न हों तो सीववाकारी राज्यों के सक्षम प्रश्चिकारी इन्हें परस्परिक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे । यह उन मामलों में भी विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।
- 4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रसकर समझौते पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ सीचे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्वेश्य से विचारों का मीखिक आदान-प्रदान उपयुक्त हो, तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

# अनुच्छेष - 26

# राजनियक और कांसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से राजनीयक अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

# अनुच्छेष -27

## प्रक्रीन

- ग्रिट्येक सीवदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपेक्षित पढितयों को पूरा करने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनाओं के बाद प्राप्त हुए अनुकर्ती मास के प्राथम विन को लागू होगा ।
- 2 इसके उपवंध इस प्रकार प्रभावी होंगे :-
  - कि के भारत में, करों के लिए उन्नीस सौ चौरानबे वर्ष के औरत मास के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में :
  - १स है तुर्की में, करों के लिए उन्नीस सी चीरानवे वर्ष के जनवरी मास के प्रथम विन को अध्या इसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक कराधेय वर्ष के संबंध में ।

# अनुच्छेद -28

#### समापन

यह करार त्व तक लागू रहेगा जब तक किसी संविदाकारी राज्य इस समाप्त नहीं कर दिया जाता है । दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने से पंच वर्षों की अविध समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्त से कम से कम छः मास पूर्व, राजनियक माध्यमों से इसकी समाप्ति का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थित में, यह करार निम्नितिस्त के लिए निध्धमायी हो जाएगा :-

- श्रक शारत में, करों के लिए जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्शी वर्ष के औरल माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले प्रत्येक पूर्ववर्शी वर्ष के संबंध में ;
- हैस है तुर्की मैं, करों के लिए जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है, उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्म होने वाले प्रत्येक कराधेय वर्ष के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से संबंधित दोनों सरकारों द्वारा प्रधिकृत अधोहस्ताक्षारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नी सी पंचानबें के जनवरी माह के इकतीसमें दिन हिन्दी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी तीनों पठ प्रमाणिक हैं । इन पठों के बीच भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पठ ही प्रमाणी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से तुर्की गणराज्य की सरकार की ओर से

Samuel

मनमोहन सिंह।

वित्त मंत्री

**∤नेकिर** सामी डांचे

राज्य मंत्री

### प्रेत<del>ीको</del>त

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए मारत गणराज्य और तुर्की गणराज्य के बीच आज इस करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरियों ने यह सहमति व्यक्त की है कि निम्निलिखत उपबंध इस करार के अभिन्न और होंगे :

- 1 अनुष्ठेद ३ के पैशाग्रफ के उप-पैशाग्रफ १ग१ के संबंध में :
  - "कर" पद में पैसी कोई साँध शाँमल नहीं होगा जो कि उन करों से संबंधत किसी चूक अथवा गलती के संबंध में देय है जिस पर यह करार लागू होता है अथवा जो अर्थ-दण्ड की राश्चि है।
- 2. अनुत्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पेराग्राफ हिन्ना के परन्तुक के संबंध में :

  यह समझा जाता है कि उसमें शामिल किसी उद्यम पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा न कि
  अनुत्छेद 12 हरायिल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसेंह और अनुत्छेद 14 हस्थतंत्र
  वैयवितक सेवाएंह के उपकंशों के अनुसार ।
- 3. अनुष्ठिद ७ के पैराग्राफ 1 के संबंध में :

यह समग्रा जाता है कि जहां किसी संविवाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होता है और, वह उद्यम –

- §क
  §
   उस दूसरे राज्य में माल अथवा उसी प्रकार की पण्य-वस्तुओं अथवा इसी प्रकार की
  वस्तुओं की विकी में प्रमाव रसता है जैसे कि वे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से
  वेची गई हैं ; अथवा
- शिल 
  शिल 
  उस दूसरे राज्य में वैसे ही अधवा उसी प्रकार के व्यावसायिक कार्यकलाप चलाता हो

  जैसा कि उस स्थायी संस्थापन माध्यम से प्रमावित हो :

ऐसी बिक्रियों और व्यावसायिक कार्यकलामें से प्राप्त लामों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन के लामों के रूप में कर लगाया जा सकता है ।

अनुस्केष ७ के पैक्याफ उ के संबंध में :

भारत में किसी स्थायी संस्थापन के संबंध में यह समझा जाता है कि भारत से बाहर उपगत कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक सर्चों पर, जिसे स्थायी संस्थापन के लामों का निर्धारण करने में कटौती दी जाएगी. निम्निलिसित कम से कम त्कम होगी :-

5.

- समायोजित कुल आय के 5 प्रतिश्वत की रकम के बराबर कोई रकम ; अधना 8 का 8
- प्रधान कार्यालय के औसत सर्चे के बराबर कोई रकम ; अधवा **१स** 8
- प्रधान कार्यालय पर उपगत व्यय के स्वरूप में ऐसे व्यय की रकम जो भारत में स्थायी 8₹ संस्थापन के कारोबार के कारण है । ऐसे किसी मामले में जहां समायोजित कुल आय हानि की स्थिति में है. तो उत्पर सण्ड १क१ के अंतर्गत स्कम को औसत समायोजित कल आय के 5 प्रतिश्वत की दर पर संगणित किया जाएगा ।

"समायोजित कुल आय", "औसत समायोजित कुल आय", "प्रधान कार्यालय के औसत सर्चे" और "प्रधान कार्यालय का व्यय" का वही अर्थ होगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिमापित है । अनुराधेव 23 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में :

> यह समझा जाता है कि अभिव्यक्ति "उन्हीं पीरीस्थितियों में" करवाता हैव्यिष्टियों, विधिक ठ्यक्तियों, भागीवारियों और संघों। का उल्लेख किया गया है जिसे उन्हीं परिस्थितियों में विधि और वस्तुत: दोनों ही पीरीस्पतियों में साधारण कराधान कानूनों और विनियमों के लागू करने की वृष्टि से रक्षा गया है।

> अन्य चीजों के साथ-साथ इसका अर्थ यह है कि दोनों राज्यों का कोई राष्ट्रिक जो किसी तृतीय राज्य का निवासी है और जो दूसरे राज्य में कारोबार कर रहा है तो उस दूसरे राज्य में उन्हीं कराधान अधवा उससे संबीधत अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा जिसके लिए उस दूसरे राज्य का कोई राष्ट्रिक जो किसी तृतीय राज्य का निवासी है और उस दूसरे राज्य में कारोबार कर रहा है, अध्यधीन है अथवा अध्यधीन हो सकता है।

यह समझा जाता है कि इस करार के उपकंध, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी बरा कृषि 6 • संबंधी कार्यकलायें से प्राप्त आय के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में लागू नहीं डोंगे ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से संबंधित दोनों सरकारों द्वरा प्रधिकृत अधोहस्तार्क्षारयों ने इस प्रेतोकोल पर इस्ताझर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नी सी पंचानवें के जनवरी माह के कक्तीसवें दिन हिन्दी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पत्न किया गया । सभी तीनों पठ प्रमाणिक हैं । इन पठों के बीच भिन्नता होने की स्थिति मैं अंग्रेजी पठ ही प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

तुर्की गणराज्य की सरकार की ओर से

वित्त मंत्री

१ बेकिर सामी हाचे १ राज्य मंत्री

[अधिसूचना सं. 10264/फा. सं. 503/1/87-वि.क. प्रभाग] एन. पी. साहनी, संयुक्त सकिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1997

INCOME- TAX

S.O. 74 (E).—Whereas the annexed Agreement between Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the first day of February, 1997, after the notification by the Contracting States to each other of the completion of the procedures required for bringing into force of the said Agreement in accordance with paragraph 1 of Article 27 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

#### **ANNEXURE**

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE

REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND THE

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO

TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

#### Article 1

#### PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

#### Article 2

#### TAXES COVERED

- This Agreement shall apply to taxes on income imposed on bohalf of a Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.
- There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises as well as taxes on capital appreciation.
- 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
- a) in the case of Turkey:
  - (i) the income tax (gelir vergisi);
  - (ii) the corporation tax (kurumlar vergisi);
  - (iii) the levy imposed on the income tax and the corporation tax

(hereinafter referred to as "Turkish tax");

- b) in the case of India:
  - (i) the income-tax including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify

each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

#### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

- 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
- a) (i) the term "Turkey" means the territory of the Republic of Turkey including any area in which the laws of Turkey are in force, as well as the maritime zones over which Turkey is entitled to sovereign rights and exercises jurisdiction in accordance with international law and Turkish law:
  - (ii) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
- b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Turkey or India as the context requires;
- the term "tax" means Indian tax or Turkish tax as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- f) the term "registered office" shall have the same meaning which it has under the laws of each Contracting State;
- g) the term "national" means any individual possessing

the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

- h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- the term "competent authority" means:
  - in Turkey, the Minister of Finance or his authorized representative;
  - (ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorized representative.
- the term "international traffic" means any transport by a ship or an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.
- 2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

#### Article 4

#### RESIDENT

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, legal head office (registered office), place of management or any other criterion of a similar nature.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
- a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States,

he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

- if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a habitual abodo;
- or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement in accordance with Article 25 of this Agreement.

#### Article 5

#### PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent establishment" includes especially:
- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources:
- h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others:
- a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;

- j) (i) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than six months; or
  - (ii) where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

Provided that for the purpose of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in that Contracting State for more than six months in connection with or supplies plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of mineral oils in the State.

- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
- the use of facilities solely for the purpose of storage, display or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery:
- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for actentific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise;

- f) the selling of goods or merchandise belonging to the enterprise displayed in an occasional temporary fair or exhibition in the process of closing down of such fair or exhibition;
- g) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (f).
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if
- a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise,
- b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, or
- c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State, shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
- 6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

# INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, fishing places of every kind, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

# Article 7

## BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment

situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

- the profits o f Я determining Īπ establishment, there shall be allowed as deductions expenses purposes of business incurred for the o f including executive and establishment, administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject limitations of the taxation laws of that State.
- 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

# Article 8

## SHIPPING AND AIR TRANSPORT

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
- 2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including:
- the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;

- b) other activity directly connected with such transportation; and
- c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.
- 3. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
- 5. For the purposes of this Article interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

#### ASSOCIATED ENTERPRISES

- 1. Where
- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reasons of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

### Article 10

#### DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, in accordance with the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident, and income derived from an investment fund and investment trust.
- 4. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other Contracting State through a permanent

establishment situated therein may, after having been taxed under Article 7 be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanent establishment is situated and in accordance with paragraph 2 of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

### Article 11

## INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:
- (a) 10 per cent of the gross amount, if such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank or a financial institution; and
- (b) 15 per cent of the gross amount in all other cases.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, provided that it is derived and beneficially owned by:
- (a) the government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State;
- (b) the Central Bank of the other Contracting State; or
- (c) the Turkish Export-Import Bank (Eximbank) and the EXIM Bank of India.
- 4. The term "interest" as used in this Article means

income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums attaching to such securities, bonds or debentures, and other income assimilated to income from money lent which is treated as interest.

- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
- Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base and such interest is borne by such permanent, establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## Article 12

# ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties or fees for technical services

may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties and fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience.
- 4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of the person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
- 6. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the right or property or contract giving rise to the royalties or fees for technical services is effectively connected, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid, having regard to the use, right, information or technical services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## Article 13

# CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the registered office of the enterprise is situated.
- 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 5 shall be taxable in the

Contracting State of which the alienator is a resident. However, the capital gains mentioned in the foregoing sentence and derived from the other Contracting State shall be taxable in the other Contracting State if the time period does not exceed one year between acquisition and alienation.

## Article 14

## INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

# Article 15

# DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16,18,19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be

taxed in that other State.

- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned in the case of Turkey and 183 days in the financial year concerned in the case of India, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the registered office of the enterprise is situated.

# Article 16

## DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a Company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

# Article 17

# ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

47

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or sportspersons if the visit to that State is substantially supported directly or indirectly by public funds of the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. In such circumstances such income shall be taxable only in the other State.

# Article 18

## NON-GOVERNMENT PENSIONS

- 1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State for his past employment may be taxed only in the first-mentioned Contracting State. This provision shall also apply to life annuities paid to a resident of a Contracting State.
- Pensions and life annuities paid, and other periodical or occasional payments made by a Contracting State, or one of its political subdivisions in respect of insuring personal accidents, may be taxed only in that State.
- 3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 4. The term' "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

## Article 19

# REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

i. a) Remuneration, other than a pension, paid by a

Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

- b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
  - (i) is a national of that State; or
  - (ti)not being the national of the first-mentioned State, did not become a resident of that State solely for purpose of rendering the services.
- 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  - b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

# Article 20

## TEACHERS AND STUDENTS

- 1. Payments which a student or business apprentice who is a national of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments arise from sources outside that other State.
- 2. Likewise, remuneration received by a teacher or by an instructor who is a national of a Contracting State and who is present in the other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in scientific research for a period or periods not exceeding two years shall be exempt from tax in

that other State on his remuneration from personal services for teaching or research, provided that such payments arise from sources outside that other State.

3. Remuneration which a student or a trainee who is a national of a Contracting State derives from an employment which he exercises in the other Contracting State for a period or periods not exceeding 183 days in a calendar year in the case of Turkey and 183 days in a financial year in the case of India, in order to obtain practical experience related to his education or training shall not be taxed in that other State.

## Article 21

## OTHER INCOME

- 1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

## Article 22

# ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provisions to the contrary is made in this Agreement.

- 2. (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Turkey, India shall allow as deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Turkey, whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, to the income which may be taxed in Turkey.
  - (b) Where a resident of India derives income which in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in Turkey, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Turkey.
- 3. Double taxation for the residents of Turkey shall be eliminated as follows:
  - where a resident of Turkey derives income covered by sub-paragraph (b) which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Turkey shall exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.
  - b) Where a resident of Turkey derives income which in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12, and paragraph 6 of Article 13 of this Agreement, may be taxed in India, Turkey shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the tax paid in India.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income-tax computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in India.

#### NON-DISCRIMINATION

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10 2. the taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.
- 3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-State are or may рe subjected í n the circumstances or under the same conditions.
- These provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other allowances, Contracting State any personal reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

## Article 24

## **EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States

shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

## Article 25

# MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

 Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or

- will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.
- competent authority shall The endeavour, 2. i f objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall implemented notwithstanding any time limits procedural limitations in the domestic law of the Contracting States, provided that the competent authority of the other Contracting State has received notification that such a case exists within five years from the end of the taxable year to which the case relates.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
- The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

## DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

## ENTRY INTO FORCE

- 1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedure required as far as it is concerned for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the first day of the following month when the latter of these notifications has been received.
- 2. Its provisions shall have effect:
- a) in Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year Nineteen Hundred Ninety-four;
- to in India, for taxes with respect to every previous year beginning on or after the first day of April of the year Nineteen Hundred Ninety-four.

### Article 28

### TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

- in Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that in which the notice of termination is given;
- b) in India, for taxes with respect to every previous year beginning on or after the first day of April of the year following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto have signed the present. Agreement.

Done in duplicate at New Dolhi this 31st day of January, 1995 in the Hindl, Turkish and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

MANMOHAN SINGH MINISTER OF FINANCE

BRKIR SAME DACE MINISTER OF STATE

## PROTOCOL

At the time of signing the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, concluded this day between the Republic of India and the Republic of Turkey, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

# 1. With respect to sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article 3:

the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty.

# 2. With respect to provise to sub-paragraph (1) of paragraph 2 of Article 5:

it is understood that an enterprise covered therein will be subject to taxation accordingly and not in accordance with provisions of Article 12 (Royalties and Fees for Technical Services) and Article 14 (Independent Personal Services).

# 3. With respect to paragraph 1 of Article 7:

it is understood that, where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, and the enterprise:

- a) effects sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or
- b) carries on other business activities in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

profits derived from such sales and business activities may be taxed in that other Contracting State as part of the profits of the permanent establishment.

# 4. With respect to paragraph 3 of Article 7:

With regard to a permanent establishment in India, it is understood that, the executive and general administrative expenses incurred outside India which will be allowed as a deduction in determining the profits of the permanent establishment shall be the least of the following amount:

- a) an amount equal to 5 per cent of the adjusted total income; or
- b) an amount equal to the average head office expenditure; or
- c) the amount of so much of the expenditure in the nature of head office expenditure incurred which is attributable to the husiness of the permanent establishment in India.

In a case where the adjusted total income is a loss, the amount under clause (a) above shall be computed at the rate of 5 per cent of the average adjusted total income. The expressions 'adjusted total income', 'average adjusted total income', 'average head office expenditure' and 'head office expenditure' will have the same meaning as defined in the Indian Income-tax Act, 1961.

# 5. With respect to paragraph (1) of Article 23:

it is understood that the expression "in the same circumstances", refers to taxpayers (individuals, legal persons, partnerships and associations) placed from the point of view of the application of the ordinary taxation laws and regulations, in substantially similar circumstances both in law and in fact.

Amongst other things this means that a national of one of the States, resident of a third State and doing business in the other State will be subjected to the same taxation or requirements connected therewith in that other State to which a national of that other State, resident in a third State and doing business in that other State, is or may be subjected.

6. It is understood that the provisions of this Agreement shall not apply to income derived by a resident of a Contracting State from agricultural activities in the other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized therete have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 31st day of January, 1995 in the Hindl, Turkish and English languages, all three texts, being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

MANMOHAN SINGH MINISTER OF FINANCE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

BEKIR SAMI DACE MINISTER OF STATE

[Notification No. 10264/F. No. 503/1/87-F.T.D.]

N. P. SAHNI, Jt. Secy.